को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण 5 और 6 में दिए गए हैं। ([देखिये परिशिष्ट CXVII अनुबंध संख्या 15]

(ख) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रादेशिक सेवा का उपग्रह आधारित टेलीकास्ट पहले ही शुरू हो गया है। तमिलनाडु में भी इसी प्रकार की सीमित सेवा शीघ्र ही शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को इन्सेट-सी के चालू हो जाने अर्थात सुविधाओं की उपलब्धता पर उपग्रह आधारित प्रादेशिक सेवा प्राप्त करने के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाड् और पंजाब में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर माइक्रोवेव लिंको के जरिए संबंधित कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों से जुड़े हुए हैं। कोचीन और कालीकट के टी.वी. ट्रांसमीटरों के वर्ष 1988-89 के दौरान माइक्रोवेव के जरिए दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम से जोड़ दिए जाने की उम्मीद है।

(ग) यदि अतिरिक्त ट्रांसपोंडर इन्सेट 1-सी में उपलब्ध हो जाएं तो 1990 के दशक के प्रारंभ में अथवा इससे पहले इन्सेट-2 के चालू हो जाने के फलस्वरूप गुजरात में सभी टी. वी. ट्रांसमेटरों के दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से जोड़ दिए जाने की परिकल्पना है।

पड़ोसी देशों द्वारा सांस्कृतिक आक्रमण

333. **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कुछ पड़ोसी देशों द्वारा अपने दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आक्रमण किये जाने के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या देश के सीमावर्ती राज्यों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) देश के कुछ सीमा क्षेत्रों में विदेशी टेलीविजन सिग्नल प्राप्त होने की सरकार की जानकारी है। अतः सातवीं योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा की किए जाने पर विशेष बल दिया गया है इस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वित होने पर देश पर सीमावर्ती जिलों की लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन द्वारा कवर किए जाने की संभावना है।

कपास का उत्पादन

334. **श्री मोर्जा ईर्शादबेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कपास का कितना उत्पादन हुआ और उसके लिये कपास उत्पादकों को प्रति क्विंटल कितना मूल्य प्राप्त हुआ;

(ख) देश को जिसी आवश्यकता की अपेक्षा यह मात्रा कितनी कम या अधिक थी; और

(ग) क्या कपास उत्पादक संघ ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ कपास उत्पादन के अनुमान नीचे दिये गये है :-

वर्ष	उत्पादन (प्रत्येक 170 किलोग्राम की लाख गांठें	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)	
		एफ. 414/ एच. 777 किस्म	एच-4 किस्म
1985-86	87.3	425	535
1986-87	70.1	430	540
1987-88	69.8 (अनंतिम)	440	550

तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों द्वारा लिये जा रहे वास्तविक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक रहे हैं।

(ख) कपास सलाहकार बोर्ड के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन में कमी आ जाने के बावजूद कुल मिलाकर कपास की उपलब्धता आगे ले जाये गये भंडार की वजह से घरेलू आवश्यता की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त थी।

(ग) आन्ध्र प्रदेश कपास संघ ने 1987 में निवेदन किया था कि कपास का उत्पादन पर्याप्त है और कपास की 10 लाख गांठ आयात करने के निर्णय को रद्द किया जाय ताकि उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु किसानों की सहायता की जा सके। सरकार ने कपास की 10 लाख गांठों का आयात करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान

335. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को राज्यवार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है तथा कितनी धनराशि बकाया है और भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें इस धनराशि का भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(ख) फसल बीमा योजना को कपास गन्ना तथा तमाम कृषि उत्पादनों तक विस्तार किये जाने के संबंध में सरकार की क्या योजना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान अदा किए गए दावों, बकाया दावों तथा उनके कारणों के ब्यौरे का राज्यवार विवरण संलग्न है। [**देखिए** परिशिष्ट अनुपत्र संख्या 16]

सरकार ने 1985-86 तथा 1986-87 के लिए सभी वैद्य दावों को पहले ही मंजूरी दे दी है। उपर्युक्त जांच के बाद शेष दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

(ख) इस समय बृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत कपास तथा गन्ना सहित अन्य किसी फसल को शामिल करने के संबंध में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

Film Festival in Sofia

336. DR. YALAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to organise film festivals in Sofia; and

(b) if so, when and names of the Indian films likely to be shown being shown there?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT).